बैंकों द्वारा किसानों से ब्याज की अधिक दर का वसूल किया जाना

118. **श्री हुक्मदेव नारायण यादव :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या यह सच है कि कुछ संसद सदस्यों ने 19 दिसम्बर, 1985 के अपने पत्र ने भूमि विकास बैंक, बिहार तथा कुछ अन्य राष्ट्रीयकृत बैंकों के विरुद्ध छोटे और सीमान्त किसानों से ब्याज की अधिक दर वसूल किये जाने तथा उन्हें अनुदानों का समय पर भुगतान न किये जाने के सम्बन्ध में आरोप लागये थे ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) एक संसद सदस्य से दिनांक 19 दिसम्बर 1985 का एक पत्र प्राप्त हुआ है जिसमें बिहार में कृषि प्रयोजनों के लिये दिए गए अग्रिमों के मामले में भूमि विकास बैंक सहित बैंकिंग प्रणाली के अधिकारियों द्वारा अपनाए गए विभिन्न भ्रष्ट तरीकों का आरोप लगाया गया है । उक्त पत्र में उठाए गए मुददों की ओर पहले भी सरकार का ध्यान आकृष्ट किया गया था और इस मामले को केन्द्रीय जांच ब्यूरों द्वारा जांच करवाई गई थी । जांच के आधार पर केन्द्रीय जांच ब्यूरों ने छः बैंक अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई करने की सिफारिश की थी । संबधित बक ने भी छः अधिकारियों के विरुद्ध मुकदमा चलाने के लिये अपनी आवश्यक सहमति दे दी थी । इस मामले की विभिन्न एजेंसियों और राज्य सरकार, केन्द्रीय जांच ब्यूरों तथा केन्द्रीय सरकार के अधिकारियों द्वारा भी जांच की गई है । इन सब जांचों के परिणामस्वरूप निष्कर्षों के आधार पर, बिहार राज्य सरकार को राज्य सरकार के संबंधित दोषी कर्मचारियों के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए भी कहा गया है ।

पर्यटन संबंधी साहित्य का अभाव

119. **श्री जगदम्बी प्रसाद यादव :** क्या **संसदीय कार्य और पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में पर्यटन सम्बन्धी साहित्य की नितान्त कमी है जिसके कारण अपने देश के तथा बाहर के देशों के लोग इस देश के रमणीक, ऐतिहासिक, भौगोलिक, सांस्कृतिक, धार्मिक तथा मनोरजक स्थलों के बारे में जानकारी प्राप्त नहीं कर पाते ;

(ख) यदि हां, तो सरकार इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाने का विचार रखती है ;

(ग) क्या यह भी सच है कि पर्यटन विभाग ने इस सम्बन्ध एक मासिक पत्रिका प्रकाशित करने का फैसला किया था और इस सम्बन्ध में सभी तैयारियां पूरी कर ली गई थीं, यदि हां, तो इस बारे में अब क्या स्थिति है ; और

(घ) क्या पर्यटन विभाग राजभाषा को बढ़ावा देने के लिए कोई प्रयास कर रहा है, यदि हां, तो इस सम्बन्ध में ब्यौरा क्या है ?

संसदीय कार्य और पर्यटन मंत्री (श्री एच०के०एल० भगत) : (क) जी नहीं । सभी प्रमुख पर्यटक केन्द्रों और साथ ही साथ कम प्रसिद्ध स्थानों गन्तव्यों को समाहित करते हुए पर्यटन विभाग के मुद्रण प्रकाशन कार्यक्रम के एक भाग के रूप में अब तक सौ से ज्यादा शीर्षक मुद्रित किए जा चुके है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) तत्कालीन पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय की हिन्दी सलाहकार समिति की सिफारिशों के अनुसरण में पर्यटन विभाग एक द्विभाषिक पत्रिका का प्रकाशन करने पर विचार कर रहा है ;

(घ) जी, हां, पर्यटन विभाग ने राजभाषा को बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठाए हैं, यथा, पर्यटक साहित्य का हिंदी में प्रकाशन, हिंदी प्रतियोगिताओं का आयोजन, अलग से एक हिंदी सलाहकार समिति की स्थापना, आदि ।

Voluntary Disclosure of concealed income

120. SHRI RAOOF VALIULLAH : Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether Government propose to do away with the system of probing into the nature and source of income disclosed by tax payers under the revised scheme of voluntary disclosure of concealed income, as stated by Shri M.S. Narayanan, Chairman, Central Board of Direct Taxes;

(b) whether appropriate instructions or circulars are being issued in this regard; if so, what are the details thereof; and

(c) whether Government propose to give the benefit of immunity from payment of penalty and prosecution for concealment of income of the current year and past years; if so, what procedure would be followed in this regard?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI JANARDHAN POOJARI): (a) The Government have assured that the assessees—both old and new—who want to come forward voluntarily to make full and true disclosure of their income can do so by filing estimates of advance tax based on true income for the current year by March 1986. It has also been clarified that such assessees would not be subjected to any roving enquiries nor would their earlier assessments be opened|reopened only on the basis of such estimates.

(b) Yes Sir. Central Board of Direct Taxes have issued circular Numbers 423 dated 26.6.1985, 432 dated 20.9.85, 440 dated 15.11.1985 and 441 dated 15.11.85 (*See below*).

(c) It has been declared that immunity from penalty and prosecution would be available till March 1986 to assessees who, before detection by the Department, come forward and declare their full and true income and pay tax thereon.

Circular No. 23

F. NO. 225|86|85-ITA. II
GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF FINANCE
DEPARTMENT OF REVENUE

CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES

NEW DELHI, THE 26TH JUNE, 1985.

SUBJECT:—Effect of higher estimates of income for purposes of advance tax in financial year 1985-86 on assessments in relation to earlier years—Clarification regarding.

The Finance Act, 1985 has, with the objective of securing better tax compliance, rationalised the rates of personal income-tax. Fears have, however, been expressed that where a tax payer declares, for purposes of payment of advance tax during the current financial year, a substantially higher income than that assessed for any earlier year, the Income-tax Officer may suspect that income chargeable to tax for that year has been under assessed and, accordingly, re-open the assessment for that year. Fears have also been expressed that where the income declared for purposes of payment of advance tax during the current financial year is higher than the income declared in the return of income for an earlier year, the Income-Tax Officer may start roving inquiries against the taxpayer in the pending assessment proceedings for that year.